

लोकसेवा शिक्षण मंडल

बनाम

ए आर मूंधड़ा चेरिटेबल ट्रस्ट

अप्रैल, 9, 2007

[सी के ठक्कर और एच एस बेदी, जेजे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-धारा 11ए- स्पष्टीकरण-कार्यवाहियों पर रोक-स्थगन आदेश की प्रकृति-नियम निसी जारी कर अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिका और स्थगन पर भी नियम जारी इसके बाद, स्टे पर नियम पर सुनवाई के लिए मामला आने पर, कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि याचिका में प्रतिवादी भवन निर्माण के लिए आगे बढ़ता है, तो यह याचिका के निर्णय के अधीन होगा- माना: कोर्ट ने किसी भी कार्यवाही के खिलाफ स्टे नहीं दिया था, केवल रूल जारी किया गया था। याचिका में की गई रोक की प्रार्थना मामले को धारा 11 ए के मुख्य भाग में कवर किया गया था न कि उसके स्पष्टीकरण में चूंकि कलेक्टर द्वारा धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर पुरस्कार नहीं दिया गया था, कार्यवाही समाप्त हो गई।

अपीलकर्ता ने सरकार से संपर्क कर भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया स्कूल के लिए भी और बगीचे के लिए भी. सरकार ने आवश्यक

कार्यवाही की दो सर्वे नंबरों की भूमि के अधिग्रहण के लिए कानून के अनुसार। सर्वे नंबर 186/4 ए में स्कूल के लिए 59 एकड़ जमीन और सर्वे नंबर 187/3 ए में बगीचे के लिए 30 एकड़ जमीन है। हेतु चिन्हित भूमि के संबंध में स्कूल के लिए उद्यान, पहले प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की दलील दी कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी का अवार्ड पारित नहीं हुआ है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11 ए के प्रावधानों के अनुसार और कार्यवाही समाप्त हो गई थी। उक्त तर्क को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और यह फैसला सुनाया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना के बाद, धारा 11 ए के अनुसार दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार दिया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि (i) अधिग्रहण को पहले प्रतिवादी द्वारा एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार किया था, और कार्यवाही की लंबितता को देखते हुए, पुरस्कार पारित किया जा सकता था भूमि अधिग्रहण अधिकारी; (ii) चूंकि पहले प्रतिवादी ने कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाया था, इसलिए वे अपनी देरी का अनुचित लाभ नहीं उठा सकते; (iii) चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई थी, इसलिए मामला धारा 11 ए के स्पष्टीकरण द्वारा कवर किया गया था, न कि धारा एलएलए के मुख्य प्रावधान द्वारा; (iv) भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि याचिका स्वीकार किए

जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई वास्तविक रोक नहीं दी गई थी, जब मामला रोक के नियम पर सुनवाई के लिए आया तो अंतरिम राहत दी गई थी; (v) भले ही रोक यथास्थिति बनाए रखने या मालिक के बेदखली के खिलाफ सीमित थी, सीमा की अवधि का विस्तार लागू होगा; (vi) उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट के अनुसरण में उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने उन्हें एक अंतरिम आदेश भेजा; (vii) भूमि अधिग्रहण अधिकारी का विचार था कि न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है और वह संबंधित फाइलों को उच्च न्यायालय के सरकारी वकील को भेजने के लिए आगे बढ़े; (viii) जब अपीलकर्ता ने भूमि अधिग्रहण की मांग की अधिग्रहण की कार्यवाही की फाइल मूवमेंट पर अधिकारी की जानकारी उच्च न्यायालय, उन्होंने जवाब दिया था कि कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया।

1. उच्च न्यायालय का यह मानना सही और पूरी तरह उचित था किसी भी कार्यवाही पर कोई रोक नहीं थी और इसलिए, धारा 11 ए के स्पष्टीकरण का कोई उपयोग नहीं था। यदि ऐसा है, तो यह नहीं माना जा सकता कि उच्च न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है या धारा 11 की गलत व्याख्या की है।

अधिनियम की धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार नहीं दिया गया, कार्यवाही समाप्त हो गई। [पैरा 32] (1022-सी-डी)

यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेंदोलिया बनाम गुजरात राज्य, (1991] 4 एससीसी 531, टी.एन. सरकार और अन्य बनाम वसंता बाई, (1995] सप्लिमेंट 2 एससीसी 423, एम)

रामलिंगा थेवर बनाम टी.एन राज्य। और अन्य, [2000] 4 एससीसी 322 और बैलम्मा (श्रीमती) @ डोड्डाबेलम्मा (मृत) और अन्य। वी. पूर्णप्रज्ञ हाउस बिल्डिंग कॉप। सोसाइटी, (2006) 2 एससीसी 416, पर भरोसा किया गया।

कमला पांडे बनाम कलेक्टर, आगरा एवं अन्य, (1989) ए डब्ल्यूसी 686, अस्वीकृत

2.1. जब अधिग्रहण की कार्यवाही को पहली बार चुनौती दी गई तो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है। अब रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट है कि पहले प्रतिवादी ने 2 अप्रैल, 1986 को उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 810/1986 दायर की थी। वह याचिका 30 अप्रैल 1986 को नियम निसी जारी कर भर्ती किया गया था। स्टे पर नियम भी जारी कर दिया गया। न्यायालय ने "किसी भी कार्यवाही" के विरुद्ध स्थगन नहीं दिया था। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में की गई

रोक की प्रार्थना पर महज नियम जारी कर दिया गया। [पैरा 22] (1019-जी; 1020-ए)

2.2. मामला 31 जुलाई, 1986 को स्थगन नियम पर सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष आया और निम्न आदेश पारित किया गया।

"प्रतिवादी नंबर 3 यदि भवन के निर्माण के साथ आगे बढ़ता है जो इस याचिका के निर्णय के अधीन होगा।" [पैरा 24] [1020-सी-डी)

2.3. उच्च न्यायालय यह कहने में सही था कि भले ही 30 अप्रैल, 1986 को आदेश दिया गया हो, स्थगन पर नियम जारी करने का मतलब यह होगा कि न्यायालय ने अनुमति दे दी है कार्यवाही पर रोक, (हालाँकि उस तारीख को कोई रोक नहीं दी गई थी), रोक संबंधी नियम को 31 जुलाई, 1986 को यह स्पष्ट करते हुए निपटा दिया गया कि कोई भी निर्माण याचिका के निर्णय के अधीन होगा। इसके बाद मामले में किसी भी तरह की रोक का कोई सवाल ही नहीं था और इस तरह मामला पूरी तरह से मुख्य रूप से कवर हो गया अधिनियम की धारा 11 ए का हिस्सा। [पैरा 31) (1022-ए-बी)

3. रजिस्ट्री द्वारा अपीलकर्ता को आदेश की संसूचना यहाँ. आमतौर पर द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में जारी की गई रिट के रूप में जाना जाता है कोर्ट ने यह नहीं बताया कि अधिग्रहण की कार्यवाही पर कोर्ट ने

रोक लगा दी है। रिट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के अनुरूप थी उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि अपीलकर्ता भवन निर्माण के लिए आगे बढ़ेगा, तो यह याचिका के निर्णय के अधीन होगा।

इस प्रकार उपरोक्त संचार अपीलकर्ता के मामले को कहीं नहीं ले जाता है। [पैरा 27) [1021-बी)

4.1. भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा सर्वे क्रमांक 187/3 ए वाली भूमि से संबंधित केस फाइल कभी नहीं भेजी गई और जो फाइल सर्वे क्रमांक 186/4 ए वाली भूमि अधिग्रहण से संबंधित भेजी गई थी। [पैरा 28) (1021-डी)

4.2. अपीलार्थी-मंडल के अध्यक्ष द्वारा भू-अर्जन अधिकारी को पत्र लिखकर फाइल मूवमेंट की जानकारी मांगी गई है। उच्च न्यायालय में अधिग्रहण की कार्यवाही, जिसका उत्तर भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा जिन कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी, वे सर्वेक्षण संख्या 186/4 ए की कार्यवाही से संबंधित थीं। (पैरा 29) [1021-ई-एफ]

4.3. उच्च न्यायालय ने 14 मार्च, 2000 को याचिका पर निर्णय लिया, जबकि अपीलकर्ता द्वारा जिस पत्र पर भरोसा किया गया है, वह स्वयं द्वारा लिखा गया था। अपीलकर्ता-मंडल ने 27 जून, 2000 को भूमि अधिग्रहण अधिकारी को जवाब भेजा और उच्च न्यायालय में रिट याचिका

के निपटारे के बाद 20 जुलाई, 2000 को भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा जवाब भेजा गया। (पैरा 30) (1021-जी)

5. कानून के प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है कि भले ही रोक यथास्थिति बनाए रखने या मालिक के बेदखली के खिलाफ सीमित थी, सीमा की अवधि का विस्तार लागू होगा। यह भी सारहीन और अप्रासंगिक है कि किस पक्ष ने ऐसा स्थगन प्राप्त किया था। (पैरा 321 (1022-सी))

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6663/2000

बॉम्बे हाई कोर्ट, नागपुर बेंच, नागपुर के की रिट याचिका संख्या 810/1986 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 14.03.2000 से।

डॉ. राजीव धवन, मकरंद डी.अदकट, विजय कुमार, भाटी त्यागी और अपीलकर्ता की ओर से विश्वजीत सिंह।

वी.एन. गणपुले, मनीष पितले, वी.एन.; रघुपति, एस.एस. शिंदे और रवींद्र सी केशवराव ने उत्तरदाताओं को आश्वासन दिया।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

सी.के. ठक्कर, जे.

1. वर्तमान अपील फैसले के खिलाफ दायर की गई है। 1986 की रिट याचिका संख्या 810 में बंबई उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) की दिनांक 14 मार्च 2000। उक्त निर्णय के द्वारा, उच्च न्यायालय ने माना

कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सर्वेक्षण संख्या 187/3 ए, मलकापुर टाउन, जिला बुलढाणा के 30 क्षेत्रों को मापता है व्यपगत हो गया था।

2. संक्षेप में कहा गया है, वर्तमान अपील की संस्था के लिए अग्रणी तथ्य यह है कि अपीलकर्ता 26 जून, 1961 को पंजीकृत एक 'सोसाइटी' है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860। इसे 17 अगस्त 1962 को बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत 'सार्वजनिक ट्रस्ट' के रूप में भी पंजीकृत किया गया है। अपीलकर्ता बुलढाणा में एक स्कूल चला रहा है। इसने सरकार से संपर्क कर स्कूल और बगीचे के लिए भी भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पत्र था अवर सचिव, राजस्व एवं वन विभाग, महाराष्ट्र शासन द्वारा लिखित ने अपीलकर्ता को भूमि अधिग्रहण के बारे में सूचित किया सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुलढाणा जिले के मलकापुर के सर्वेक्षण क्रमांक 186 और 187, अर्थात्. अपीलकर्ता द्वारा एक स्कूल चलाने के लिए। अपीलार्थी द्वारा यह कहा गया कि प्रतिवादी अधिकारियों ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना और विकास अधिनियम, 1966 के तहत मलकापुर टाउन की अंतिम विकास योजना तैयार की, जिसमें सर्वेक्षण संख्या 186/4 ए की 59 एकड़ भूमि और सर्वेक्षण संख्या 187/3 ए की 30 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। स्कूल और खुली जगह के प्रयोजन के लिए अपीलकर्ता के लिए बगीचे के लिए। 15 मई 1976 का एक संकल्प भी था विकास योजना को मंजूरी देते हुए

पारित किया गया। आवश्यक कार्यवाही इसके बाद भूमि अधिग्रहण के लिए कानून के अनुसार कार्यवाही की गई। जहां तक स्कूल के लिए सर्वे नंबर 186/4 ए की 59 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का सवाल है, यह सवाल अब विवाद में नहीं है। इसे अंतिम रूप दे दिया गया था और उक्त अधिग्रहण की चुनौती विफल रही। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में कहा है कि उसकी राय में, "कोई दोष नहीं पाया जा सकता है 59 एकड़ भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिकारी के फैसले के साथ।" इसलिए, इस हद तक, यहां पहले प्रतिवादी (मूल याचिकाकर्ता) द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई। सर्वेक्षण संख्या की 30 एकड़ भूमि के संबंध में 187/3 ए स्कूल के लिए बगीचे के लिए निर्धारित है, पहले प्रतिवादी मूल याचिकाकर्ता का तर्क था कि पुरस्कार पारित नहीं किया गया था भूमि अधिग्रहण की धारा 11 ए के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और कार्यवाही समाप्त हो गई।

उक्त तर्क को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और यह फैसला सुनाया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना के बाद, धारा 11 ए के अनुसार दो साल की निर्धारित अवधि के भीतर पुरस्कार दिया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया और इसलिए कार्यवाही समाप्त हो गई। उच्च न्यायालय का निर्णय इस हद तक था कि सर्वेक्षण संख्या 187/3 ए की 30 एकड़ भूमि के संबंध में कार्यवाही समाप्त हो गई थी,

अपीलकर्ता-मंडल व्यथित है और उसने वर्तमान अपील दायर करके इसे चुनौती दी है।

3. प्रतिष्ठानों के बीच विवाद में नहीं है कि प्राधिकृतियों ने दो सर्वे नंबरों की ज़मीन के अधिग्रहण के लिए प्राधिकृतियों द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी (i) सर्वे नंबर 186/4A, जो 59 एकड़ ज़मीन के लिए थी; और (ii) सर्वे नंबर 187/3A, जो 30 एकड़ ज़मीन के लिए थी। वर्तमान अपील में जिस हाईकोर्ट के निर्णय से स्पष्ट है कि हालांकि पहले उत्तराधिकारी ने दोनों सर्वे नंबरों के लिए ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध किया था, हाईकोर्ट ने सभी आपत्तियों को इनकार किया कि सर्वे नंबर 186/4A के 59 एकड़ की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ था और यह याचिका खारिज की गई थी। सर्वे नंबर 187/3A के 30 एकड़ की ज़मीन के लिए ही महकमा ने कहा कि हालात यह हैं कि, यद्यपि धारा 6 के तहत अधिसूचना 2 जुलाई 1986 को प्रकाशित की गई थी, तथाकथित कानून के अनुसार दो वर्षों के भीतर कोई पुरस्कृत नहीं किया गया था और प्रक्रिया समाप्त हो गई थी।

4. 28 जुलाई 2000 को, मामला प्रवेश सुनवाई के लिए रखा गया था। सूचना जारी की गई और प्रतिष्ठानों को स्थिति को बनाए रखने के लिए निर्देश दिया गया। 20 नवंबर 2000 को, अनुमति दी गई और अंतरिम राहत जारी रखने का आदेश दिया गया। मामला अब अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया है।

5. हमने प्रतिष्ठानों के वकीलों की बात सुनी है।

6. डॉ. राजीव धवन, अपेक्षित अपीलकर्ता के रूप में उपस्थित सीनियर एडवोकेट ने यह दावा किया कि हाईकोर्ट ने धारा 11A के तहत प्रक्रिया की विफलता का कानूनी और क्षेत्राधिकार में एक अपराध किया है। यह दावा किया गया कि महकमा को ध्यान में रखना चाहिए था कि पहले उत्तराधिकारी ने एक रिट पिटीशन दायर करके अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध किया था, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकृत किया था। प्रक्रिया के पंडुलिपि के कारण, ज़मीन अधिग्रहण अधिकारी द्वारा कोई पुरस्कृत नहीं किया जा सकता था और धारा 11A का अनुप्रयोग नहीं था। यह भी कहा गया कि एकतरफा पहला उत्तराधिकारी ने प्रक्रिया का विरोध किया और अंतरिम राहत प्राप्त की और दूसरी ओर, उसने यह कहने की कोशिश की कि क्योंकि प्रक्रिया को कानूनी रूप से पूरा नहीं किया जा सका, वे समाप्त हो गई थीं। ऐसे तर्क, वकील ने दावा किया, उस व्यक्ति की ज़बान में नहीं बैठता जिसने प्रक्रिया की विधि का सवाल किया था। यह स्थिर कानून है कि प्रतिष्ठान अपने विलंब का अत्यधिक फायदा नहीं उठा सकती है। हाईकोर्ट को इस तथ्य को समझना चाहिए था और यह याचिका खारिज करनी चाहिए थी अनुसार अपीलकर्ता, जब प्रक्रिया हाईकोर्ट में प्रवृत्त हो रही थी और मामला सब जूडिस था, जमीन अधिग्रहण अधिकारी ने पुरस्कृत करने में न्याय था। एक बार जनसार प्रदान किया गया और धारा 6 के

तहत अधिसूचना प्रकाशित हो गई थी. इसे एक विशेषक्षेत्र पर स्थापित नहीं किया जा सकता था या नहीं। इसलिए, यह दावा किया गया कि अपील को हाईकोर्ट के निर्णय को खारिज करके और प्राधिकृतियों के क्रियावली को कानून के साथ मेल खाते हुए अनुमति देना चाहिए कि ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया कानून के साथ थी।

7. दूसरी ओर, पहले प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया। उनके मुताबिक धारा 11 ए की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है. अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर पुरस्कार देना भूमि अधिग्रहण अधिकारी का अनिवार्य कर्तव्य है। चूँकि ऐसा नहीं किया गया, कार्यवाही समाप्त हो गई थी। वकील ने कहा कि माना कि उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई थी। यदि ऐसा है, तो अधिनियम की धारा 11 ए के स्पष्टीकरण का कोई उपयोग नहीं होगा और धारा 11 ए के तहत दो साल की अवधि की गणना में, रिट याचिका की लंबित अवधि को बाहर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने कहा कि अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने अपने हलफनामे में तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, पहले प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी। रिट याचिका के लंबित होने के आलोक में,

अधिकारियों ने अधिग्रहण की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया और पहला प्रतिवादी, जिसने कार्यवाही को चुनौती दी थी, उस स्थिति का लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने याचिका को अनुमति देने में गलती की।

9. इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को सही ठहराया था जो अधिनियम की धारा 11ए के तहत दिया जाना चाहिए था, जो निर्धारित अवधि के भीतर नहीं दिया गया था। इस संबंध में दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने हमारा ध्यान कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ इस न्यायालय के निर्णयों की ओर भी आकर्षित किया।

10. अब यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक राज्य के पास उत्कृष्ट डोमेन की शक्ति है, जो संप्रभुता का आवश्यक गुण है। उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपनी प्रजा की निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक उद्देश्य' को अधिनियम की धारा 3 के खंड (एफ) में परिभाषित किया गया है। धारा 4 'उपयुक्त सरकार' को 'प्रारंभिक अधिसूचना' जारी करने में सक्षम बनाती है यदि ऐसी सरकार को लगता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भूमि की आवश्यकता है या होने की संभावना है। अधिनियम की धारा 5ए प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियों की सुनवाई का प्रावधान करती

है। धारा 6 'उचित सरकार' को 'अंतिम अधिसूचना' जारी करने का अधिकार देती है। हालाँकि, ऐसी कार्रवाई, अधिनियम की धारा 5 ए के तहत कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद की जानी है। यह अधिसूचना के प्रकाशन के तरीके भी प्रदान करता है और उप-धारा (3) में एक प्रावधान है कि ऐसी घोषणा 'इस बात का निर्णायक सबूत होगी कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है'। कानून में जमीन का कब्जा लेने से पहले इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस देने और मुआवजे के भुगतान का भी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 11 कलेक्टर द्वारा मुआवजा देने से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम 68) द्वारा सम्मिलित धारा 11 ए उस अवधि को निर्धारित करती है जिसके भीतर कलेक्टर द्वारा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उक्त अनुभाग सारगर्भित है और इसे विस्तार से उद्धृत किया जा सकता है:-

"11 ए। वह अवधि जिसके भीतर पुरस्कार दिया जाएगा (1) कलेक्टर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर धारा 11 के तहत एक पुरस्कार देगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो संपूर्ण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां उक्त घोषणा भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 68) के प्रारंभ होने से पहले प्रकाशित की गई हो, पुरस्कार ऐसे प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण। इस धारा में निर्दिष्ट दो वर्षों की अवधि की गणना करते समय, वह अवधि, जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दी जाती है, को बाहर रखा जाएगा।"

11. अधिनियम की धारा 12 कलेक्टर के पुरस्कार को अंतिम बनाती है। हम वर्तमान मामले में अधिनियम के अन्य प्रावधानों से चिंतित नहीं हैं।

12. धारा 11ए को मात्र पढ़ने से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि कलेक्टर को अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार देने का आदेश दिया गया है। "यदि उस अवधि के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। हालाँकि, धारा 11ए के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि दो साल की अवधि को कैसे गिना जाना चाहिए। यह स्पष्ट करता है कि धारा में

निर्दिष्ट दो वर्षों की अवधि की गणना करते समय, वह अवधि, जिसके दौरान किसी अदालत के आदेश द्वारा किसी कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है, को बाहर रखा जाएगा। जबकि पहले प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामला धारा 11 ए के मुख्य प्रावधान द्वारा शासित होता है, अपीलकर्ता का तर्क यह है कि यह उक्त प्रावधान के स्पष्टीकरण द्वारा शासित होता है।

13. आइए अब प्रावधान की व्याख्या पर इस न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों पर विचार करें। युसुफभाई नूरमोहम्मद नेंदोलिया बनाम गुजरात राज्य, [1991] 4 एससीसी 531 में, एक प्रश्न संभवतः पहली बार इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। उस मामले में, अपीलकर्ता की भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और अधिनियम की धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना 12 मई, 1988 को जारी की गई थी। भूमि मालिक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अधिसूचना को चुनौती दी थी। गुजरात का अधिसूचना एवं अधिग्रहण की कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना की गई। रिट याचिका के लंबित रहने और अंतिम निपटान के दौरान, अधिसूचना के संचालन और कार्यान्वयन की अंतरिम राहत भी मांगी गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका लंबित रहने तक अधिकारियों को भूमि पर कब्जा करने से रोककर सीमित अंतरिम राहत दी। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने भूमि के मुआवजे का निर्धारण करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 9 की उप-

धारा (1) के तहत एक नोटिस जारी किया। पूछताछ में भूमि-मालिक ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन के बाद दो साल बीत चुके थे और इसलिए, कोई पुरस्कार पारित नहीं किया जा सका क्योंकि धारा 11 ए के तहत कार्यवाही समाप्त हो गई थी। हालाँकि, भूमि-मालिक के तर्क को अधिकारियों ने खारिज कर दिया। उक्त निर्णय को भूमि-मालिक ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर करके चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि अदालत द्वारा अधिकारियों पर रोक लगाते हुए 'आगे की कार्यवाही' पर कोई रोक नहीं थी और इसलिए अधिकारियों के लिए अधिनियम के तहत आगे बढ़ना अनिवार्य था। चूँकि ऐसा नहीं किया गया था, धारा 11ए के अनुसार पुरस्कार दो साल के भीतर दिया जाना चाहिए था।

चूँकि अधिनियम की धारा 11ए द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पुरस्कार पारित नहीं किया गया था, इसलिए इसे वैधानिक सीमा द्वारा रोक दिया गया और कार्यवाही समाप्त हो गई। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि "धारा 11ए का स्पष्टीकरण अधिसूचना की धारा 6 के अनुसार पुरस्कार देने पर रोक लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक रूप से शब्दों में लिखा गया है और इसमें पूरी अवधि शामिल है, जिसके दौरान कोई भी धारा 6 के तहत घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कार्रवाई या कार्यवाही पर सक्षम

न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है।" इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि पुरस्कार वैधानिक अवधि से आगे चला गया है, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला। पीड़ित भूमि मालिक ने उक्त फैसले को इस न्यायालय में चुनौती दी।

14. इस न्यायालय को इस बात पर विचार करने के लिए बुलाया गया था कि क्या उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 11ए के स्पष्टीकरण को लागू करने में सही था, हालांकि सीमित अंतरिम राहत केवल कब्जे के लिए दी गई थी और 'आगे की कार्यवाही' पर रोक नहीं लगाई थी। भूमि-स्वामी की ओर से, एस बावजन साहिब बनाम केरल राज्य, एआईआर (1988) केआर 280 में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था कि भूमि पर कब्जा लेने का सवाल केवल तभी उठता है जब कोई धारा 17 (तत्काल के मामले) के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर अधिनियम के तहत पुरस्कार पारित किया जाता है। जब अधिनियम की धारा 17 लागू नहीं की गई थी, तो मामला अधिनियम की धारा 11ए द्वारा शासित होगा, न कि उसके स्पष्टीकरण द्वारा और यदि धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अधिनियम, कार्यवाही समाप्त हो जायेगी। हालाँकि, इस न्यायालय ने इस विवाद को खारिज कर दिया, केरल के दृष्टिकोण से असहमति जताई और कहा; "हम उपरोक्त फैसले में केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमत होने में खुद को

असमर्थ पाते हैं।" न्यायालय ने तब अधिनियम की योजना और अधिसूचना के अनुसरण में की जाने वाली वाक्यांश "कोई कार्रवाई या कार्यवाही" पर विचार किया और माना कि भले ही सीमित अंतरिम राहत दी गई हो, धारा 11 ए का स्पष्टीकरण लागू होगा।

15. स्पष्टीकरण की उदारतापूर्वक व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने कहा;

"उक्त स्पष्टीकरण यथासंभव व्यापक शब्दों में है और, हमारी राय में, उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार देने से पहले की कार्रवाई या कार्यवाही के लिए स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कार्रवाई या कार्यवाही को सीमित करने का कोई वारंट नहीं है। पहला स्थान, जैसा कि स्वयं विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आयोजित किया गया है, जहां मामला धारा 17 के अंतर्गत आता है, एक पुरस्कार दिए जाने से पहले कब्जा लिया जा सकता है और हमें कोई कारण नहीं दिखता है कि स्पष्टीकरण में पूर्वोक्त अभिव्यक्ति को अलग-अलग अर्थ क्यों दिया जाना चाहिए इस पर कि क्या मामला धारा 17 के अंतर्गत आता है या अन्यथा। दूसरी ओर, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 11-ए का उद्देश्य उस भूमि धारक को दिए जाने वाले लाभ को

सीमित करना है जिसकी भूमि धारा 6 के तहत घोषणा के बाद अर्जित की गई है।

स्पष्टीकरण में शामिल मामलों में। लाभ यह है कि पुरस्कार घोषणा के दो साल की अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए, अन्यथा अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और भूमि भूमि-धारक को वापस कर दी जाएगी। उक्त प्रावधान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक यह है कि लाभ चाहने वाले भूमि-धारक ने उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के अनुसरण में किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अदालत से कोई आदेश प्राप्त नहीं किया हो। ताकि स्पष्टीकरण केवल उन भूमि-धारकों के मामलों को कवर करे, जिन्होंने अदालत से कोई आदेश प्राप्त नहीं किया है जो पुरस्कार देने या अधिग्रहित भूमि पर कब्जा लेने में देरी करेगा या रोक देगा। हमारी राय में, गुजरात उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में समान दृष्टिकोण अपनाते हैं सही था।"

16. टी.एन. सरकार में और अन्य. बनाम वसंता बाई, [1995] सप्लिमेंट 2 एससीसी 423, इसी तरह की स्थिति में, इस न्यायालय ने यूसुफभाई में निर्धारित सिद्धांत को दोहराया और देखा कि अधिनियम की

धारा 11 ए के तहत पुरस्कार देने के लिए दो साल की सीमा अवधि की गणना करते समय, वह अवधि जिसके दौरान उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, को बाहर रखा जाएगा। यह माना गया कि भले ही केवल बेदखली के संबंध में रोक लगाई गई हो, यह आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के समान होगा और पूरी अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए।

17. एम. रामालिंगा थेवर बनाम टी.एन. राज्य में और अन्य, [2000] 4 एससीसी 322: जेटी (2000) 5 एससी 27, इस न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 11 ए के स्पष्टीकरण के अनुसार, समय से बहिष्करण की अवधि वह अवधि है जिसके दौरान "कोई भी कार्रवाई या कार्यवाही" की जाती है। उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। निस्संदेह, धारा 6 के तहत घोषणा के अनुसार विचार की जाने वाली कार्रवाइयों में से एक भूमि पर कब्जा करना है, हालांकि ऐसी कार्रवाई सामान्य परिस्थितियों में पुरस्कार के बाद का कदम है। बहरहाल, यह अधिनियम की धारा 6 द्वारा परिकल्पित घोषणा के अनुसरण में अनुवर्ती उपाय के रूप में अपनाई जाने वाली कार्रवाइयों में से एक है। यह देखते हुए कि धारा 11 ए में उल्लिखित परिणाम एक स्व-संचालित वैधानिक प्रक्रिया है, न्यायालय ने कहा कि यह केवल तभी संचालित हो सकती है जब इसमें निर्दिष्ट शर्तें एक साथ मिलती हैं। परिणाम तभी सामने आएंगे जब उसमें निर्धारित सभी शर्तों का एकीकरण

हो जाएगा। यदि घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई रोक है तो चूक का परिणाम नहीं होगा।

इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:-

"इस प्रकार, स्थिति अब अच्छी तरह से तय हो गई है कि भले ही अकेले बेदखली पर अदालत द्वारा रोक लगा दी जाती है, जिस अवधि के दौरान इस तरह की रोक लागू होती है, उसे पुरस्कार पारित करने के लिए निर्धारित समय से बाहर रखा जाएगा, जिसकी समाप्ति से अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।"

18. हाल ही में, बैलम्मा (श्रीमती) @ डोड्डाबेलम्मा (मृत) और अन्य में। वी. पूर्णप्रज्ञ हाउस बिल्डिंग कॉप। सोसाइटी, [2006] 2 एससीसी 416: जेटी (2006) 2 एससी 108, यह माना गया है कि घोषणा के अनुसरण में की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक की अवधि मामले को मुख्य भाग से धारा 11ए में ले जाएगी। उक्त धारा में स्पष्टीकरण को आकर्षित करने वाला अधिनियम।

कोर्ट ने कहा;

इस न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि धारा 11ए को भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पुरस्कार देने में की जाने वाली अत्यधिक देरी को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो मालिकों को संपत्ति के

आनंद से वंचित करता है या उस भूमि से निपटने के लिए जिसका कब्जा पहले ही लिया जा चुका है। पुरस्कार देने से भूमि के मालिक को अनकही कठिनाई का सामना करना पड़ा। अधिनियम में धारा 11ए को शामिल करने के उद्देश्य और कारण यह थे कि "अधिग्रहण की कार्यवाही लंबे समय तक लंबित रहने से अक्सर प्रभावित पक्षों को कठिनाई होती है और उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे का पैमाना अवास्तविक हो जाता है" और "एक अवधि प्रदान करने का प्रस्ताव है अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि जिसके भीतर कलेक्टर को अधिनियम के तहत अपना पुरस्कार देना चाहिए। इसलिए, जोर इस बात पर था कि कलेक्टर निर्धारित अवधि के भीतर अपना पुरस्कार दे। हालाँकि, विधायिका भी स्थिति की वास्तविकता से अवगत थी और इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थी कि कई मामलों में इच्छुक पार्टियों द्वारा कानून की अदालतों से प्राप्त स्थगन आदेशों के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही रुकी हुई थी। इसलिए, यह जरूरी हो गया कि दो साल की अवधि की गणना करते समय, वह अवधि जिसके दौरान स्थगन आदेश लागू हुआ, जिसने अधिकारियों को घोषणा के अनुसरण में कोई कार्रवाई करने या आगे बढ़ने से रोका, को बाहर रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था, तो स्थगन आदेश प्राप्त करके और उसके बाद मुकदमेबाजी को लम्बा खींचकर अधिग्रहण की कार्यवाही को आसानी से विफल किया जा सकता है।

धारा 11ए का स्पष्टीकरण इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए था। स्पष्टीकरण यथासंभव व्यापक शब्दों में है जो इसके संचालन को उन मामलों तक सीमित नहीं करता है जहां अकेले भूमि-मालिक द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया जाता है। ऐसे मामलों की कल्पना की जा सकती है जहां भूमि मालिकों के अलावा अन्य लोग भी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकने में रुचि रखते हों। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश रिपोर्ट किए गए निर्णयों में जिस पक्ष ने स्थगन आदेश प्राप्त किया था, वह अधिग्रहित भूमि का मालिक था। लेकिन इससे हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे कि स्पष्टीकरण केवल उन मामलों पर लागू होता है जहां जमीन के मालिकों द्वारा स्थगन प्राप्त किया गया था। ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जो अधिग्रहण की कार्यवाही से व्यथित होकर स्थगन आदेश प्राप्त करने में रुचि रखते हों। ऐसा हो सकता है कि उस क्षेत्र के विकास के कारण आसपास के कुछ लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, या यह किसी अन्य कारण से हो सकता है कि जिस परियोजना के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, उससे इलाके के लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हों। कोई ऐसे कई उदाहरणों की कल्पना कर सकता है जिनमें मालिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अधिग्रहण की कार्यवाही को विफल करने में रुचि रखता हो। एक बार जब स्थगन आदेश प्राप्त हो जाता है और सरकार और कलेक्टर को घोषणा के अनुसार कोई भी आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है, तो उन्हें देरी के लिए दोषी नहीं

ठहराया जा सकता है, और इसलिए, जिस अवधि के दौरान स्थगन आदेश लागू होता है, उसे बाहर रखा जाना चाहिए। एक तरह से, स्थगन आदेश का क्रियान्वयन अधिग्रहण की कार्यवाही में आगे कदम उठाने में देरी का औचित्य प्रदान करता है जिसके लिए अधिकारी दोषी नहीं हैं।

19. डॉ. धवन ने श्रीमती में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के एक फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। कमला पांडे बनाम कलेक्टर, आगरा एवं अन्य, (1989) एडब्ल्यूसी 686। उस मामले में, अधिनियम की धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर कोई पुरस्कार पारित नहीं किया गया था। इसलिए, भूमि मालिक की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 11ए के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई थी। हालाँकि, न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक 'तकनीकी याचिका' थी और अधिकारियों की ओर से चूक यह थी कि "विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने याचिकाकर्ता के भूखंड के संबंध में मुआवजे का निर्धारण इस आधार पर नहीं किया था" कि प्रश्न क्या संपत्ति को अधिग्रहण से छूट दी जानी चाहिए, यह राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

न्यायालय ने तब कहा:-

"इसलिए, विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या याचिकाकर्ता ने स्वयं भूमि को अधिग्रहण से छूट देने का अनुरोध किया था या विकास प्राधिकरण या कलेक्टर ने स्वयं ही सरकार से अधिग्रहण से छूट देने का अनुरोध किया था।

मानव का सामान्य पाठ्यक्रम आचरण हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जिन व्यक्तियों की जमीन या घर छीने जा रहे हैं, वे ही भूमि को अधिग्रहण से छूट दिलाने में रुचि रखते हैं। आमतौर पर, किसी को भी अधिग्रहण पसंद नहीं है, भले ही उसे अधिग्रहण के बदले मुआवजा मिल जाए। हम करेंगे, इसलिए, आगरा विकास प्राधिकरण के संस्करण पर भरोसा करना पसंद करेंगे कि यह याचिकाकर्ता और अन्य थे जिनके कहने पर मामला उनकी भूमि की छूट के लिए सरकार को भेजा गया था। किसी भी दर पर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सके आगरा विकास प्राधिकरण की तुलना में याचिकाकर्ताओं के संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी।"

20. यह भी देखा गया कि जब भूमि मालिक ने स्वयं अधिग्रहण के खिलाफ सरकार से संपर्क करके पुरस्कार देने में देरी में योगदान दिया, तो कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सका।

कोर्ट ने कहा:-

"यह चूक कानून के साथ धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि इस विचार के आधार पर स्पष्ट रूप से प्रामाणिक थी कि भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के लिए एक कदम उठाया गया था। इसके अलावा, जो व्यक्ति अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने से प्रभावित होंगे, वे हैं हमारे सामने नहीं। इस स्थिति में कार्यवाही को रद्द करना, हमारे विचार में, उचित नहीं होगा। यदि हम तकनीकी आधार पर कार्यवाही को रद्द कर देते हैं, यह मानते हुए कि पुरस्कार देने में चूक हुई है, तो यह व्यापक सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाएगा। याचिकाकर्ताओं की भूमि के संबंध में समय के भीतर संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रभाव उत्पन्न हुआ।

21. इस तथ्य के अलावा कि उपरोक्त निर्णय का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है, प्रश्न अब एकीकृत नहीं है और अंततः यूसुफभाई में इस न्यायालय द्वारा तय किया गया था और समय-समय पर दोहराया गया

था। इसलिए, हमारी राय में, उपरोक्त निर्णय से अपीलकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी।

22. हमारी सुविचारित राय में, डॉ. धवन का यह तर्क देना भी सही नहीं है कि चूंकि अंतरिम राहत दी गई थी, इसलिए मामला धारा 11ए के स्पष्टीकरण द्वारा कवर किया गया था, न कि धारा 11ए के मुख्य प्रावधान द्वारा। इसलिए, पहले प्रतिवादी द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दिए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है। अब रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रथम प्रतिवादी ने 2 अप्रैल 1986 को उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 810/1985 दायर की।

30 अप्रैल 1986 को न्यायालय ने नियम जारी करके याचिका को स्वीकार कर लिया और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"नियम। संबंधित मामले के साथ रखा जाए। स्थगन पर नियम। अवकाश न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता।" (जोर दिया गया)

23. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिका नियम निसी जारी करके स्वीकार की गई थी। स्टे पर नियम भी जारी कर दिया गया। हालाँकि, हमारी राय में, पहले प्रतिवादी के विद्वान वकील का यह तर्क सही है कि न्यायालय ने "किसी भी कार्यवाही" के विरुद्ध स्थगन नहीं दिया है।

याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में की गई रोक की प्रार्थना पर महज नियम जारी कर दिया गया।

24. मामला 31 जुलाई, 1986 को स्थगन नियम पर सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष आया और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

"प्रतिवादी नंबर 3 यदि भवन के निर्माण के लिए आगे बढ़ता है तो यह इस याचिका के निर्णय के अधीन होगा।"

25. डॉ. धवन ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि 30 अप्रैल, 1986 को न्यायालय द्वारा कोई वास्तविक रोक नहीं दी गई थी, अंतरिम राहत 31 जुलाई, 1986 को दी गई थी। उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया। यहां अपीलकर्ता को रजिस्ट्री द्वारा आदेश का संचार, आमतौर पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में जारी रिट के रूप में जाना जाता है। संचार में अन्य बातों के अलावा कहा गया है।

"21 अप्रैल, 1986 को इस उच्च न्यायालय बॉम्बे में प्रस्तुत आवेदक की याचिका को पढ़ने पर प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी नंबर 2 और उसके संस्थानों और उसके कर्मचारियों, एजेंटों, नौकरों आदि को प्रकृति को बदलने से रोका जाए। अनुबंध-एल में भूमि अधिग्रहण मामले संख्या

एलएक्यू/मलकापुर/4/1977-78 में दिनांक 27.2.1986 के कथित पुरस्कार द्वारा संदर्भित सर्वेक्षण संख्या 186/4 ए और 187/3 ए से 0.59 माप वाली भूमि का संबंध तब तक है जब तक इस याचिका का निर्णय और इस याचिका के निर्णय तक इसमें बदलावों पर कोई भी निर्माण करने से उन्हें रोका जाएगा"

तब कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था:-

"तदनुसार यह निर्देशित किया जाता है कि यदि आप भवन निर्माण के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यह इस याचिका के निर्णय के अधीन होगा।"

26. डॉ. धवन ने प्रस्तुत किया कि यह उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा अपीलकर्ता को सूचित एक अंतरिम आदेश था।

27. रिट को पढ़ने पर भी, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा उपरोक्त संचार में यह नहीं कहा गया था कि अधिग्रहण की कार्यवाही न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी। हमारी राय में, रिट, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के अनुरूप थी और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि अपीलकर्ता भवन के निर्माण के साथ आगे बढ़ेगा, तो यह याचिका के निर्णय के अधीन होगा। इस प्रकार उपरोक्त संचार अपीलकर्ता के मामले को कहीं नहीं ले जाता है।

28. तब डॉ. धवन द्वारा यह तर्क दिया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी का विचार था कि न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है और वह संबंधित फाइलों को उच्च न्यायालय के सरकारी वकील को भेजने के लिए आगे बढ़े। इसके लिए, वकील ने फैसले में बताए गए तथ्यों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हालांकि अदालत से कोई विशेष आदेश नहीं था, सरकारी वकील के एक अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी को मामले का रिकॉर्ड भेजने के लिए एक पत्र जारी किया गया था। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि सर्वेक्षण संख्या 187/3 ए वाली भूमि से संबंधित केस फाइल भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा कभी नहीं भेजी गई थी और जो फाइल सर्वेक्षण संख्या 186/4 ए वाली भूमि के अधिग्रहण से संबंधित भेजी गई थी।

29. अपीलकर्ता ने अपीलकर्ता-मंडल के अध्यक्ष द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी को 27 जून 2000 को लिखे एक पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें उच्च न्यायालय में अधिग्रहण की कार्यवाही की फाइल मूवमेंट के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसका जवाब भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने दिया था। 20 जुलाई, 2000 को लिखे अपने पत्र में कहा गया है कि 1986 की रिट याचिका संख्या 810 में उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। पत्र से, यह स्पष्ट है कि यह सर्वेक्षण संख्या 186/4 ए की कार्यवाही से संबंधित है। लेकिन अन्यथा भी, न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल स्पष्ट था। न्यायालय द्वारा कोई

रोक नहीं दी गई थी, और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता था कि धारा 11ए का स्पष्टीकरण आकर्षित हुआ और ऐसी अवधि को दो साल की अवधि की गणना से बाहर रखा जाएगा।

30. यह भी कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने 14 मार्च, 2000 को याचिका पर निर्णय लिया, जबकि अपीलकर्ता द्वारा जिस पत्र पर भरोसा किया गया है, वह अपीलकर्ता-मंडल द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी को 27 जून, 2000 को लिखा गया था और उत्तर दिया गया था। उच्च न्यायालय में रिट याचिका के निस्तारण के बाद 20 जुलाई 2000 को भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भेजा गया था।

31. हमारी राय में, इसलिए, उच्च न्यायालय यह देखने में सही था कि भले ही 30 अप्रैल, 1986 के आदेश में, स्थगन पर नियम जारी करने का मतलब यह होगा कि न्यायालय ने कार्यवाही पर स्थगन दे दिया था, (हालाँकि उस तारीख को कोई स्थगन नहीं दिया गया था) 31 जुलाई, 1986 को स्थगन नियम को यह स्पष्ट करते हुए निस्तारित कर दिया गया कि कोई भी निर्माण याचिका के निर्णय के अधीन होगा। इसके बाद मामले में किसी भी रोक का सवाल ही नहीं था और इस तरह यह मामला पूरी तरह से अधिनियम की धारा 11ए के मुख्य भाग के अंतर्गत आता था।

32. यह आग्रह किया गया कि 'स्टे' शब्द की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा की गई थी व्यापक रूप से और यह माना गया कि भले ही रोक यथास्थिति बनाए रखने या मालिक के बेदखली के खिलाफ सीमित थी, सीमा की अवधि का विस्तार लागू होगा। कानून के उक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है। यह भी सारहीन और अप्रासंगिक है कि किस पक्ष ने ऐसा स्थगन प्राप्त किया था। एकमात्र सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक लगाई गई थी। हमारे सामने मौजूद मामले में, उच्च न्यायालय यह मानने में पूरी तरह से सही और न्यायसंगत था कि किसी भी कार्यवाही पर कोई रोक नहीं थी और इसलिए, धारा 11ए के स्पष्टीकरण का कोई उपयोग नहीं था। यदि ऐसा है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने कानून की गलती की है या धारा 11ए की गलत व्याख्या की है, क्योंकि धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार नहीं दिया गया था। अधिनियम, कार्यवाही व्यपगत। चूंकि अपीलकर्ता की वर्तमान अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून के अनुरूप है, इसलिए अपील खारिज की जानी चाहिए।

33. उपरोक्त कारणों से, हमें उच्च न्यायालय के आदेश में कोई खामी नहीं दिखती। अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार, लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज की जाती है।

वी एस एस

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल शसुवासश् की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ० मनोज सिंघारिया (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।